



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उद्देश्य (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रांगिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, भैंगलधार, मई 22, 1990/ज्येष्ठ 1, 1912

No. 270]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 1990/JYAISTHA 1, 1912

इस भाग के बिना दुष्क संस्था वी जाती है कि यह असम विभाग के द्वारा रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

प्रधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 22 मई, 1990

का.मा. 399(ग्र):—“दल खालसा” नामक संगठन—

(1) जिसने एक पूर्ण स्वायत्त “खालसा राज्य” की स्थापना करना अपना एक मुख्य उद्देश्य घोषित किया है और अपने उद्देश्य के अनुसरण में अपने क्रियाकलापों से भारत की गणराज्योन्नीय अवसंदेता से बिलग होने और उसे विभाजित करने का उद्देश दे रहा है;

(2) जिसके प्रधानिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान के लिए अपने बाले सिक्कड़ लड्डू समूहों के मध्य एकता को आवश्यकता पर बल देकर “खालिस्तान” के बनाए जाने का समर्थन किया है, यिदेशी सुनाचारपत्रों और गुरुद्वारा मठों से खालिस्तान असमर्थ प्रचार को झड़ाया है और भारत सरकार से कोई वातव्रीत न करने के लिए छपकियां दी हैं,

(3) जिसने पुलिस अधिकारियों और उनके मुख्यमंत्रियों को मारने के लिए खालिस्तान-समर्थक सिक्कड़ समूहों की एक कार्रवाई समिति गठित की है;

(4) जिसके कार्यकर्ता प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं “जिसमें भारत खालिस्तान छोड़ो;” जैसे नारे लगाए गए थे, पंजाब में खालिस्तान के लिए लड़ने वाले लड्डू सिक्कड़ों को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभाएं आयोजित की गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से दल खालसा एक विधिविरुद्ध संगठन है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि दल खालसा के क्रियाकलापों के कारण दल खालसा को तान्त्रिक प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है;

ग्रन्त: श्रब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप तिनार्हम प्रशिक्षियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त गणित्यों का प्रदान

करते हुए, दल खालसा को एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुकृ द्वारा प्रदत्त शास्त्रियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधिकारीन रहने हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाय, राज्यपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होती।

[का सं. 1/1701/29/89-आई एम (डी-7)]

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd May, 1990

S.O. 399 399 (E).—Whereas the organisation known as the 'Dal Khalsa'—

- (i) which had declared as its main objective the establishment of a complete autonomous 'Khalsa State' and in pursuance of its objective has been preaching secession and disruption of the territorial integrity of India through its activities;
- (ii) whose office bearers and activists have extended support to the creation of 'Khalistan' by stressing the need for unity between Sikh militant groups fighting for Khalistan, stepping up pro-Khalistan propaganda through foreign press and Gurdwara platforms and warning against negotiations with the Government of India;
- (iii) which formed an Action Committee of the pro-Khalistan Sikh militant groups to kill police officers and their informers;
- (iv) whose activists have been holding demonstrations in which slogans like 'India quit Khalistan' were raised, holding meetings for providing more financial aid to the Sikh militants fighting for Khalistan in Punjab;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Dal Khalsa is an unlawful association.

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the activities of the Dal Khalsa, it is necessary to declare the Dal Khalsa to be 'unlawful with immediate effect';

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Dal Khalsa to be an unlawful association and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section that this Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. I/17017/29/89-IS (D. VII)]

का. आ. 400 (ग्र):—“नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान” नामक संगठन, जिसे इसमें उसके पश्चात् “काउंसिल” कहा गया है;

- (i) जिसने अपने मैकेटरी जनरल थी इन्डिया मिह संघ की घोषणा से अपने उद्देश्य एक स्वायत्त पृथक खालिस्तान सिक्ख राज्य की घोषना की उद्घोषणा की थी, अलगाववादी क्रियाकलापों को प्रोत्तमाहन दे रही है;
- (ii) जिसका प्रैमिडेंट डा. जगजीत सिंह चौहान विदेशी समाचार पत्रों के माध्यम से खालिस्तान के सविचार को फैला रहा है;
- (iii) जिसके निर्वाचित रिपब्लिक आफ खालिस्तान सरकार के कार्यवाहक प्रैमिडेंट ने बद्र दाता किया है कि भारतीय धर्मों को गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 1989) को यू. के. के सभी गुरुद्वारों में जलाया गया था;
- (iv) जिसके विदेशों में बसे कार्यकर्ता और नदाधिकारी जलूसों के द्वारा खालिस्तान-मध्यके और भारत-विरोधी नारे लगा रहे हैं, पंजाब से खालिस्तान के लिए लड़ने वाले लड़ाकू लिक्खों की सहायता के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं;
- (v) जिसके निर्वाचित खालिस्तान सरकार के कार्यवाहक प्रैमिडेंट ने 30 जनवरी, 1989 को यू. के. से भारत के नत्कालीन प्रधान मंत्री को खालिस्तान के चिन्ह के साथ निर्वाचित खालिस्तान सरकार के पत्र-पैड पर एक चूला पत्र भेजा जिसमें खालिस्तान के भारत के कठजों को तुरंत खाली करने के लिए भारत सरकार से प्राहृत्वान किया था और जिसका प्राइम मिनिस्टर सिक्खों की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए विश्व समुदाय से नैतिक और धन संवंधी सहायता का प्राप्तवान कर रहा है;
- (vi) जिसके पदाधिकारी खालिस्तान को मांग को दोहराते रहे हैं और जिन्होंने आयोजित क्रेतन्शन के द्वारा पंजाब में खड़ाकू सिखों के परिवारों को धन दिए जाने की श्रील की है;
- (vii) जिसके संयुक्त राज्य अस्थित आज़सिम आफ “खालिस्तान”, जो संयुक्त राज्य अमरीका में नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान की एक शाखा है, का प्रैमिडेंट भास्त में ध्वंसक स्वतंत्रता/सामरी भेज रहा है; जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह खाली किया गया है कि खालिस्तान को क्योंकि भारत में स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है, इसलिए इसको मान्यता मिलाना केवल कुछ समय की ही बात रह गई है, इस समय बर्तमान पंजाब एक बखलकृत राज्यक्षेत्र है और यह कि दोनों

सरकारों के बीच सीमाओं को मिक्कड़ गढ़ के माथ बातचीत के जरिए उपदेशित किया जाना चाहिए ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पुर्ववित कारणों में परिषद् एक विधिविहृद्ध समग्र है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह और राय है कि परिषद् के प्रेजिडेंट और अन्य कार्यकर्ताओं के वार्तालाप, कथनों, लेखनों और अन्य क्रियाकलापों के कारण परिषद् को नामानुक्रम प्रभाव में विधिविहृद्ध घोषित करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविहृद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शर्यतों का प्रयोग करते हुए, नेशनल कार्डिनल आफ ब्रालिस्टान को एक विधिविहृद्ध संगम घोषित करती है और इस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शर्यतों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अध्यधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, गज़पत्र में इसके प्रकाशन की नारीख्त में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 1/17017/29/89-आई एस (डी-7)]

अशोक भट्टा, संयुक्त सचिव

S.O. 400 (E).—Whereas the organisation known as the 'National Council of Khalistan' hereinafter referred to as the 'Council'—

- (i) which had through the declaration of Shri Balbir Singh Sandhu, its Secretary General, proclaimed its objective the establishment of an autonomous separate Sikh State of 'Khalistan' has been encouraging secessionist activities ;
- (ii) whose President Dr. Jagjit Singh Chauhan has been spreading the concept of 'Khalistan' through foreign press ;
- (iii) whose acting President of the Government-in-exile of the 'Republic of Khalistan' claimed that Indian flags were burnt in all Gurdwaras of the United Kingdom on Republic Day (26th January, 1989) ;
- (iv) whose activities and office bearers abroad have been raising pro-'Khalistan' and anti-India slogans during processions, collecting

funds in the aid of Sikh militants fighting for 'Khalistan' in Punjab ;

- (v) whose acting President of the 'Khalistan' Government-in-exile sent an open letter on 30th January, 1989 to the then Prime Minister of India from the United Kingdom on the letter pad form of the 'Khalistan' Government-in-exile with 'Khalistan' insignia urging the Indian Government to vacate the Indian occupation of 'Khalistan' without further delay and whose Prime Minister has been calling for moral and material support from the world communities to the Sikh war of independence ;
- (vi) whose office bearers have been reiterating the demand for Khalistan, appealing for money to be given to the families of Sikh militants in Punjab during convention organised by them ;
- (vii) whose President of the United States based Council of 'Khalistan', a branch of the National Council of Khalistan in the United States of America has been sending to India subversive literature/material in which, among other things, it has been claimed that 'Khalistan' has since been declared independent from India, its recognition is only a matter of time, at present Punjab is an occupied territory and that the boundaries between the two Governments should be marked through negotiations with Sikh Nation ;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Council is an unlawful association ;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the talks, utterances, writings and other activities of the President and other activists of the Council, it is necessary to declare the Council to be unlawful with immediate effect ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Council of Khalistan to be an unlawful association and directs in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section that this Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/17017/29/89-IS (D. VII)]  
ASHOK BHATIA, Jt. Secy.

